



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

ल० 30]

मई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 19, 1990/पौष 29, 1911

No. 30] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 19, 1990/PAUSA 29, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वाली जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त संबंधी
(प्राधिकार कार्य विभाग)
(विक्रिग प्रभाग)
गोदान

मई दिल्ली, 19 जनवरी, 1990

का. आ. 31(अ) वैकारी वित्तियमन अधिनियम, 1919 (1949
का 10) की धरण 56 के विषय (मर्यादा) के साथ पटिन धारा 15 को
उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त लक्षितों का प्रयोग करने से हुए, कर्त्रीय
भक्तार उक्त धारा 15 की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारतीय वित्त
वैकारी वित्त शास्त्र आवेदन पत्र पर विचार करने के द्वारा बांद्रा पीपल्स
कोर्टेजेटिव बैंक दि. श्रीद्वारा, वर्म्बर-400050 (जिसे इसके पश्चात्
'भक्तारी बैंक' कहा गया है) के संबंध में एन्ड्रेडा 19 जनवरी, 1990
को यैक का कारोबार बैंक होने से लेकर 19 मई, 1990 तक और
उस दिन की गिला कर अधिनियमन आदेश जारी करनी है, जिसके अन-
भार अधिनियमन आदेश की अवधि के दौरान भक्तारी बैंक के विच्छेन मर्मा
कार्यवालों का यह किया जाना अथवा यह की गई कार्रवाइयों को
जारी रखना चाहिये किया जाना है, तिन्हीं मने यह है कि इस प्रकार
के अधिनियमन का किसी भी प्रकार गो महाराष्ट्र बोर्डरेटिव संगठन

अधिनियम 1960 के अन्तर्गत महाराष्ट्र भक्तार द्वारा प्रयोग में लाए
जाने वाले उसके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े।

2. केंद्रीय भक्तार, एन्ड्रेडा यह निवेदण देता है कि स्वीकृत अधि-
स्थगन की अवधि के दौरान यह भक्तारों बैंक, भोर्नीय रिजर्व बैंक की
नियमित पूर्वानुमति के बिना कोई अथवा अधिम नहीं होगा, किसी
अधिम का नवीकारण नहीं करेगा, बैंक की किसी परिमाणात्मक का अन्य
संकलन अथवा निपटान नहीं करेगा, किसी प्रभाव या विप्रिय रवीकार
नहीं करेगा, कोई निवेदण नहीं करेगा अथवा आपने दियत्वों और देत-
करियों के संबंध में अथवा अन्यथा किसी प्रकार की अवायी नहीं करेगा
अथवा अदायी करते स्वीकार नहीं करेगा अथवा किसी प्रकार
का भमसीता अथवा टहराव नहीं करेगा किन्तु यह निम्नलिखित तरीके
से और निम्नलिखित गंभीर तक प्रथारिति अवायीयां अवाया अर्व
करेगा :

(1) प्रथेक बैंक अथवा जानू खाते अथवा किसी भी नाम
से पुकारे जाने वाले किसी अन्य जमा खाते की शेष रकम में से 250 रुपये
में अनन्तिक राशि, जिसमें 26 दिसम्बर, 1987 के बाद भुगतान की गई
राशि यदि कोई हो, शामिल है, करने द्वारा वापसते कि अदा की गई रकम
की छुल सीमा किसी एक व्यक्ति (किसी अन्य अधिकृत के माध्यम संग्रहन जाने
में नहीं) के नाम से खाते में जमा कुल राशि 250/- रुपये से अधिक
न हो।

यह भी शर्त है कि ऐसे किसी व्यक्ति को कोई रकम आदा नहीं की जाएगी जो किसी प्रकार से सहकारी बैंक का कर्तव्य हो;

(2) ऐसे किसी दैनिक द्वारा, पेशीदे अथवा दैनिक गो शण जो सहकारी बैंक द्वारा 26 दिसंबर, 1987 को आर्ग कर दिया गया है, और जिसका उम तारीख तक भुगतान नहीं किया गया है, जिसकी अधिस्थगत आदेश लागू होता है।

(3) 26 दिसंबर, 1987 को अथवा उससे पूर्व भुगतान के लिए प्राप्त हुए होंगों की गणि चाहे वे उम तारीख से पहले, उम तारीख को या उम तारीख के बाद बसूत की गई हों।

(4) ऐसा कोई व्यय जो किसी सहकारी बैंक के द्वारा उसके अथवा उसके विरुद्ध दापत किया गया सूक्ष्म, अपेक्षित अथवा सहकारी बैंक द्वारा या उसके विरुद्ध जी गई उपर्योगी या बैंक को मिलने धारी किसी रकम या बसूत करने के संबंध में करना आवश्यक हो, वहाँ कि प्रत्येक सूक्ष्म, अपील अथवा डिक्टी के संबंध में किए जाने वाले व्यय की रकम 600/- रुपये से अधिक हो, तो अर्च करने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक का लिखित अनुमति जी जाएगी;

(5) ऐसा कोई व्यय जो शिला, शिवा और प्रत्यय गार्डी निगम को देव प्रोत्साहन की गणि हो; या

(6) किसी अन्य मद पर कोई व्यय, जहाँ तक कि वह आप सहकारी बैंक के विचार में बैंक का दैनिक प्रशासन चलाने के लिए करता अनुमति हो।

वहाँ कि जहाँ किसी एक बैंलेण्डर माम से किसी मद पर किया गया कुल छंच अधिस्थगत आदेश से पहले के छंच बैंलेण्डर महंतों में उम मद पर किया गया अन्य मामिक व्यय से बह जाता हो, अथवा उसे अवधि के दौरान जहाँ उम मद पर कोई व्यय नहीं किया गया हो या उस प्रकार किया जाने जाना व्यय 250/- रुपये से बह जाए तो उस प्रकार का व्यय करने से पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित रूप में अनुमति जी जाएगी।

3. केंद्रीय सचिव एवं दूसरे यह भी निवेद देनी है कि सहकारी बैंक की संवर्कन अधिस्थगत की अवधि के दौरान :

(क) यह सहकारी बैंक निम्नलिखित और प्रदायगियों का संकेत अथवा संस्कारी प्रतिभूतियों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के बदले महाराष्ट्र सरकार अथवा महाराष्ट्र स्टेट कॉम्पोनेटिव प्रोफेसनल बैंक लि. या टार्ड इंट्रीक्ट सेंट्रल कॉम्पोनेटिव बैंक लि. टार्ड अथवा भारतीय स्टेट बैंक अथवा हस्तक्षेत्री सहायता बैंकों या किसी अन्य बैंक द्वारा सहकारी बैंक को किया गया अर्णों अथवा अविभागों जो अधिस्थगत आदेश के प्रभावों होने की तारीख को चुकाए जाने में थे, को वापसी आदेशी के लिए आवश्यक हो।

(ख) सहकारी बैंक को पूर्णोंका अद्यगियां करने के लिए महाराष्ट्र स्टेट कॉम्पोनेटिव प्रोफेसनल बैंक लि. अथवा किसी अन्य बैंक के साथ अपने आपने चलाने की अनुमति दी जाएगी।

परन्तु इस आदेश का ऐसा कोई आवश्यक नहीं होता कि इस बैंक सहकारी को किसी रकम के लिए जाने से पहले महाराष्ट्र स्टेट कॉम्पोनेटिव प्रोफेसनल बैंक लि. अथवा किसी अन्य बैंक को इस अवधि में अपने आपको आपसन करना होता कि इस आदेश द्वारा लगाई गई शर्तों का इस बैंक द्वारा पालन किया जा रहा है।

(ग) यह सहकारी बैंक, उन हुए होंगों को, जो बसूत न की गई हों, उसको प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति के अनुग्रह पर सौदा संकेत या इस सहकारी बैंक का उन हुए होंगों पर कोई प्रधिकार अथवा हक न हो अथवा जैसी हुए होंगों में उसका कोई हित न हो।

(घ) सहकारी बैंक ऐसे मात्र अथवा प्रतिभूतियों को जो इस (बैंक) के पास किया गया, नकदी, कार्ड अथवा शोवर ड्राफ्ट के बदले गिरवा, दैनिक अथवा बंधक रखा गई हो अथवा प्रत्यया प्राप्ति गई हो जो निम्नलिखित मामियों में स्ट्रोड अथवा दें भाग :

(1) किसी ऐसे मामियों में जहाँ यथास्थिति अण्डरलान्डों में मिलने वाली गारी रकम सहकारी बैंक द्वारा ग्रिता जाने शर्त की गई हो; और

(2) किसी अन्य मामियों में, उन भीमा तक को रकम दिलाना आवश्यक अथवा सम्भव हो, जिविट अनुपातों में नीचे अवधि उन अनुपातों से नीचे, जो अधिस्थगत प्रादेश के प्रभावी होने से पहले लागू था, हनमें जी भी ऊंचे हों, उन मात्र शोर प्रतिभूतियों पर मार्जिन के अनुपातों को कम किया जिता।

[पा सं. 6-4/89-7, नी.]

प्रधीन शुभार सेजपान, अप्र० मविक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

ORDER

New Delhi, the 19th January, 1990

S.O. 51(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 45, read with clause (zb) of section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, after considering the application made by the Reserve Bank of India under sub-section (1) of the said section 45, hereby makes an order of moratorium in respect of the Bandra People's Co-operative Bank Ltd., Bandra, Bombay-400 050 (hereinafter referred to as the Co-operative Bank) for the period from close of business on the January 19, 1990 upto and inclusive of the May 19, 1990 staying the commencement or continuance of all actions and proceedings against the Co-operative Bank during the period of moratorium, subject to the condition that such stay shall not in any manner prejudice the exercise by the Government of Maharashtra of its powers under the Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960.

2. The Central Government hereby directs that, during the period of the moratorium granted to it, the Co-operative Bank shall not, without the prior permission in writing of the Reserve Bank of India, grant any loan, make or renew any advance, alienate or dispose of any assets of the said Bank, incur any liability, make any investment or make or agree to make any payment, whether in discharge of its liabilities or obligations or otherwise, or enter into any compromise or arrangement, except making of payments, or incurring of expenditure, as the case may be, to the extent and in the manner provided hereunder :—

(i) Out of the balance in every savings bank or current account or in any other deposit account, by whatever name called, a sum not exceeding Rs. 250 including the amount, if any, paid after 26th December, 1987.

Provided that the sum total of the amounts paid in respect of the accounts standing in the name of any one person (and not jointly with that of any other person) does not exceed Rs. 250;

Provided further that no amount shall be paid to any depositors who is indebted to the Co-operative Bank in any way;

- (ii) the amounts of any drafts or pay orders or cheques issued on or before 26th December 1987 by the Co-operative Bank and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force;
- (iii) The amounts of the bills received for collection on or before 26th December 1987 whether realized before, on or after that date;
- (iv) any expenditure which has necessarily to be incurred in connection with any suits or appeals filed by or against, or decrees obtained by or against, the Co-operative Bank, or for realizing any amounts due to it;

Provided that if the expenditure in respect of each such suit or appeal or decree is in excess of Rs. 600/-, the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before the expenditure is incurred;

- (v) the amount of premium payable to Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation; and
- (vi) any expenditure on any other item in so far as it is in the opinion of the Co-operative Bank necessary for carrying on the day-to-day administration of the Co-operative Bank;

Provided that where the total expenditure on any item in any calendar month exceeds the average monthly expenditure on account of that item during the six calendar months preceding the order of moratorium, or where no expenditure has been incurred on account of that item during the said period and the expenditure on such item exceeds the sum of Rs. 250/-, the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before the expenditure is incurred.

3. The Central Government hereby also directs that, during the period of moratorium granted to it, the Co-operative Bank—

- (a) may make the following further payments, namely, the amounts necessary for repaying

loans or advances granted against Government securities or other securities to the Co-operative Bank by the Government of Maharashtra or the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd. or Bombay District Central Co-operative Bank Ltd., or the State Bank of India or any of its subsidiaries or by any other and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force;

- (b) may operate its accounts with the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd., or with any other bank for the purpose of making the payments aforesaid;

Provided that nothing in this order shall be deemed to require the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd., or such other bank to satisfy itself that the conditions imposed by this order are being observed before any amounts are released in favour of the Co-operative Bank;

- (c) may return any bills which have remained unrealized to the persons entitled to receive them on a request being made in this behalf by such persons, if the Co-operative Bank has no right or title to, or interest in such bills;

- (d) may release or deliver goods or securities which have been pledged, hypothecated or mortgaged or otherwise charged to it against any loan, cash credit or overdraft, in the manner and to the extent—

- (i) in any case in which full payment towards all the amounts due from the borrower or borrowers, as the case may be, has been received by the Co-operative Bank, unconditionally, and
- (ii) in any other case, to such an extent as may be necessary or possible, without reducing the proportions of the margins on the said goods or securities below the stipulated proportions, or the proportions which were maintained before the order of moratorium came into force, whichever may be higher.

[F. No. 6-4/89-AC]

P. K. TEJYAN, Under Secy.

